



राजपत्र हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, २ अगस्त, १९९६/११ भावण, १९१८

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-१७१००२, २७ मई, १९९६

संख्या एल० एल० आर० (राजभाषा) (बी०) १६-३/९६.—हिमाचल प्रदेश रेस्ट्रिक्शन आफ मोटगेज लैंडिंग ऐक्ट, १९७६ (१९७६ का २०) के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तारीख १४-५-१९९६ के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है

और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश बंधकित भूमि प्रत्यास्थापन अधिनियम, 1976

(1976 का 20)

(-----को यथा विद्यमान)

अस्तित्वयुक्त बंधक के अधीन भूमि के प्रत्यास्थापन का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश बंधकित भूमि प्रत्यास्थापन अधिनियम, 1976 है ।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ ।

(2) इसका विस्तार पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, यह अधिनियम भूमि के किन्हीं अस्तित्वयुक्त बंधकों को जो उस तारीख से 20 वर्ष पूर्व किए गए थे जिसने इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन बंधकित भूमि के कब्जे के प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन किया गया है, लागू होगा ।

अधिनियम
का अस्तित्वयुक्त
बंधक को
लागू होना ।

स्पष्टीकरण.—बंधक, इस बात के होते हुए भी, कि इस के मोचन के लिए डिक्री या आदेश पारित कर दिया गया है, अस्तित्व में समझा जाएगा, परन्तु यह तब जबकि मोचन इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व न हो गया हो ।

3. (1) शब्द “भूमि” से वह भूमि अभिप्रेत है जो नगर या ग्राम में किसी भवन के स्थल के रूप में अधिभोग में नहीं है और जो कृषि प्रयोजन या कृषि उपयोगी प्रयोजन अथवा चरागाह के लिए अधिभोग में है या किराए पर दी गई है और निम्नलिखित इसके अन्तर्गत हैं —

परिभाषाएं ।

- (क) ऐसी भूमि पर भवनों और अन्य संरचनाओं के स्थल ;
- (ख) सम्पदा या घृति के लाभ में कोई अंश ;
- (ग) निम्नतर भू-स्वामी द्वारा उच्चतर भू-स्वामी को संदेय किसी देय भू-राजस्व की कोई नियत प्रतिशतता ;
- (घ) किराया प्राप्त करने का अधिकार ;
- (ङ) भू-स्वामी या अधिभोगी द्वारा इस रूप में जल के उपभोग का कोई अधिकार ;
- (च) अधिभोग का कोई अधिकार ; और
- (छ) ऐसी भूमि पर खड़े सभी वृक्ष ।

(2) शब्द “कलैक्टर” से उस जिले का कलैक्टर अभिप्रेत है जिसमें बंधकित सम्पत्ति या उसका कोई भाग स्थित है और उसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के

प्रयोजन के लिए कलैक्टर के कर्तव्यों के पालन के लिए विशेष रूप से सशक्त प्रथम श्रेणी सहायक कलैक्टर है ।

(3) शब्द "आयुक्त" से उस क्षेत्र का आयुक्त अभिप्रेत है जिसमें बंधकित सम्पत्ति या उसका कोई भाग स्थित है और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आयुक्त के कर्तव्यों के पालन के लिए विशेष रूप से सशक्त कोई अधिकारी है ।

(4) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।

(5) "बंधककर्ता" या "बंधकदार" के अन्तर्गत क्रमशः ऐसे 'बंधककर्ता' या 'बंधकदार', का यथा स्थिति, समनुदेशिनी और हितप्रतिनिधि है ।

प्रत्यास्थापन
याचिका ।

4. कोई बंधककर्ता जिसकी भूमि को इस अधिनियम के उपबन्ध लागू है किसी भी समय बंधकित भूमि के कब्जे के प्रत्यास्थापन के लिए याचना करते हुए याचिका उपस्थापित कर सकेगा । याचिका ऐसी याचिकाओं के लिए विहित रीति में सम्यक् रूप से सत्यापित होगी ।

प्रत्यास्थापन
याचिका पर
कार्यवाही ।
कीप्रक्रिया

(5) कलैक्टर ऐसी याचिका की प्राप्ति पर, ऐसी जांच के पश्चात जो विहित की जाए, कारणों सहित यह कथन करते हुए कि क्या प्रश्नगत बंधक ऐसा है जिसे यह अधिनियम लागू है आदेश अभिलिखित करेगा ।

याचिका कब
खारिज की
जाएगी ।

(6) यदि कलैक्टर यह निष्कर्ष निकालता है कि बंधक ऐसा है जिसे यह अधिनियम लागू नहीं है तो, वह याचिका खारिज कर देगा ।

कलैक्टर की
बंधककर्ता के
पक्ष में आदेश
घोषित और
प्रवर्तित करने
और कतिपय
मामलों में
बंधकदार
को प्रतिकर
देने की
शक्ति ।

7. (1) यदि कलैक्टर यह निष्कर्ष निकालता है कि बंधक ऐसा है जिसे यह अधिनियम लागू है तो, वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिती में किसी बात के होते हुए भी, उन मामलों में जहां वह यह निष्कर्ष निकालता है कि कब्जे के दौरान बंधकदार द्वारा उपभोग किए गए फायदे का मूल्य, बंधक के अधीन मूलतः उधार दी गई राशि के डुगने के समान है या उससे अधिक है तो वह लिखित रूप में आदेश करेगा कि—

(क) बंधक को निर्वापित किया जाए ; और

(ख) जहां बंधकदार का उस समय भी कब्जा है, वहां बंधकदार के स्थान पर, बंधककर्ता को बंधकित भूमि का कब्जा दिया जाए और हक-विलेख, यदि कोई हो, बंधककर्ता को वापस किए जाएं ।

(2) यदि उन मामलों में जिनको यह अधिनियम लागू है, कलैक्टर यह निष्कर्ष निकालता है कि कब्जे के समय बंधकदार द्वारा उपभोग किए गए फायदे का मूल्य, मूलतः उधार दी गई मूल राशि के डुगने से कम है और बंधक के निबन्धनों के अनुसार बंधकदार को अभी भी कुछ देय है तो कलैक्टर लिखित आदेश द्वारा और तत्समय

प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी निर्देश देगा कि बंधक-कर्ता द्वारा बंधकदार को निम्नलिखित मापमान से अनधिक दरों पर प्रतिकर के संदाय के अधीन बंधककर्ता को भूमि प्रत्यावर्तित की जाए और उसे कब्जा दिया जाए :—

- (i) यदि बंधकदार का बीस वर्ष से अधिक किन्तु पच्चीस वर्ष से अनधिक काला-वधि के लिए कब्जा रहा है, बंधकित किए जाने के समय भूमि पर निर्धारित राजस्व का तीस गुना ;
- (ii) यदि बंधकदार का पच्चीस वर्ष से अधिक कालावधि के लिए कब्जा रहा है, बंधकित किए जाने के समय भूमि पर निर्धारित राजस्व का पन्द्रह गुना ।

स्पष्टीकरण—कलैक्टर इस धारा के प्रयोजन के लिए कब्जे की कालावधि को, बंधक-दार के कब्जा लेने की तारीख से धारा 4 के अधीन याचिका के प्रस्तुतीकरण की तारीख तक संगणित करेगा ।

8. यदि कलैक्टर यह निष्कर्ष निकलता है कि धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन प्रतिकर के रूप में बंधकदार को कोई राशि देय है तो वह बंधककर्ता से रकम को ऐसी रीति से जो विहित की जाए, जमा करने की अपेक्षा करेगा । और रकम जमा किए जाने पर वह बंधकदार के अधिकारों को निर्वापित घोषित करेगा और बन्धकदार से भूमि से संबंधित सभी दस्तावेजों सहित बंधककर्ता को भूमि का कब्जा देने की अपेक्षा करेगा ।

जब प्रतिकर संदेय हो प्रत्यास्थापन के आदेश का प्रभाव ।

9. कलैक्टर बंधकदार के अधिकारों को निर्वापित घोषित करने के पश्चात् बंधक-दार को बेदखल कर सकेगा और बंधककर्ता को, बंधकित भूमि का कब्जा परिदत्त करने का आदेश करेगा । प्रतिरोध करने की दशा में कलैक्टर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के नियम 97 और 98 द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

कलैक्टर की बंधकदार बेदखल करने की शक्ति ।

10. इस अधिनियम के अधीन किए गए मूल या अपीलीय आदेश से निम्नलिखित को अपील होगी, अर्थात् :—

अपील ।

(क) आयुक्त को जब आदेश कलैक्टर द्वारा किया गया हो ;

(ख) वित्तायुक्त को जब आदेश आयुक्त द्वारा किया गया हो :

परन्तु जब प्रथम अपील पर मूल आदेश की पुष्टि की गई हो तो आगे अपील नहीं होगी ।

11. वित्तायुक्त किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किए गए आवेदन पर, इस अधिनियम के अधीन लम्बित या विनिश्चित किसी मामले के अभिलेख मंगवा सकेगा और ऐसे किसी मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे :

पुनरीक्षण ।

परन्तु वह इस धारा के अधीन सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना किन्हीं कार्यवाहियों या आदेश को बदलने या परिवर्तन करने का आदेश पारित नहीं करेगा ।

अपील की परिसीमा । 12. (1) पूर्वगामी अन्तिम धारा के अधीन अपील की परिसीमा की अवधि, उस आदेश की तारीख से आरम्भ होगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है और निम्न प्रकार से होगी:—

- (क) जब अपील आयुक्त को हो—साठ दिन ;
- (ख) जब अपील वित्तायुक्त को हो—नब्बे दिन ।

(2) इस धारा के अधीन परिसीमा अवधि संगणित करते समय उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, प्रतियां प्राप्त करने के लिए अपेक्षित अवधि अपवर्जित की जाएगी ।

(3) इस अधिनियम के अधीन सभी अपीलों को, भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 का 36 1963 की धारा 5 के उपबन्ध लागू होंगे ।

सिविल न्यायालय की 13 किसी सिविल न्यायालय को, इस अधिनियम के अधीन निर्वाचित घोषित किसी बंधक के अधीन किसी अधिकार को प्रवर्तित करने के किसी दावे को ग्रहण करने या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही की वैधता को प्रश्नगत करने की, अधिकारिता का वर्जन । नहीं होगी ।

नियम बनाने की शक्ति । 14. (1) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से, नियम बना सकेगी ।

(2) विनिश्चित और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार निम्नलिखित विषयों को विनियमित और अवधारित करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् :—

- (क) इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन याचिका का उपस्थापन और सत्यापन,
- (ख) प्रक्रिया जिस द्वारा कलैक्टर अधिनियम की धाराएं 5, 6 और 7 के अधीन ऐसी याचिकाओं का निपटारा करेगा और प्रतिकर का, यदि कोई हो, अवधारण करेगा ;
- (ग) प्रक्रिया और सिद्धान्त जिन द्वारा कलैक्टर बंधक के अधीन देय रकम का और कब्जे के समय बंधकदार को प्रोदभूत होने वाले फायदों के मूल्य का निर्धारण करेगा ;
- (घ) इस अधिनियम की धारा 8 द्वारा विहित राशि जमा करने की प्रक्रिया; और
- (ङ) इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन बंधकदार की बेदेखली को प्रवर्तित करने और बंधकर्ता को कब्जा परिदत्त करने की प्रक्रिया ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में किसी परिवर्तन

की अपेक्षा करती है तो तत्पश्चात् नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि विधान सभा चाहती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात को विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

15. हिमाचल प्रदेश (विधियों का लागू होना) आदेश, 1948 द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू पंजाब रैस्ट्रिटीयूशन आफ मोर्टगेजड लैंड ऐक्ट, 1938 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 द्वारा हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों को यथा लागू पंजाब रैस्ट्रिटीयूशन आफ मोर्टगेजड लैंड ऐक्ट, 1938 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है :

निरसन और व्यावृत्तियाँ ।

परन्तु इस प्रकार निरसित अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन या द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए की गई कोई बात, कार्यवाही, बनाए गए नियम या जारी की गई अधिसूचना, उस विस्तार तक जहाँ तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत है, इस अधिनियम के अधीन या द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई, बनाए गए या जारी की गई समझी जाएगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस को ऐसी बात या कार्यवाही की गई थी नियम बनाए गए थे या अधिसूचना जारी की गई थी ।

